आकाशवाणी शिमला

18.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

मुख्य समाचार

- प्रदेश विधानसभा ने विपक्ष के भारी हंगामे और शोरगुल के बीच केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करने का सरकारी संकल्प किया पारित।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा–विधायक क्षेत्र विकास निधि की शेष दो किस्तें 31 मार्च से पहले की जाएंगी जारी।
- प्रदेश के सेब बागवानों को ठगी से बचाने के उद्देश्य से लाईसेंस बनाने के लिए बैंक गारंटी की शर्त में बदलाव करेगी राज्य सरकार।
- चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की–हिमाचल की एकमात्र सीट के लिए 16 मार्च को होगा मतदान।
- लाहौल स्पिति की पट्टन घाटी में फागली व चम्बा की पांगी घाटी में जुकारू पर्व की धूम।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ऐलान किया कि उनकी पूरी कैबिनेट सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आरडीजी की बहाली के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को तैयार है। शिमला में आयोजित प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरडीजी को लेकर सदन में बीते तीन से चल रही चर्चा का उत्तर देते हुए आज मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275 और 280 के तहत आरडीजी हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि यहां की जनता का हक है। इस दौरान सदन में विपक्ष के भारी हंगामे और शोरगुल के बीच केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान को बहाल करने का सरकारी संकल्प पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आरडीजी एक बार बंद हो गई तो इसे दोबारा बहाल नहीं करवाया जा सकेगा और इसका असर प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय प्रदेश को 54 हजार करोड़ रुपए आरडीजी के रूप में और 16 हजार करोड़ रुपए जीएसटी मुआवजे के रूप में मिले, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसका सदुपयोग नहीं किया। इसके विपरीत मौजूदा कांग्रेस सरकार को आरडीजी के रूप में सिर्फ 17 हजार करोड़ रुपए ही मिला।

उन्होंने कहा कि यदि भाजपा ने प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए होते तो वह इस राशि से कर्ज को काफी कम कर सकती थी, क्योंकि पांच साल की अवधि में भाजपा सरकार ने 45 हजार करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया। मुख्यमंत्री ने भाजपा से आग्रह किया कि वह आरडीजी बहाल करवाने के मौके को हाथ से न जाने दें और यदि ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ियां उसे माफ नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। बाद में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की बैठक 18 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की एक करोड़ 10 लाख रुपए की शेष दो किस्तें 31 मार्च से पहले जारी कर दी जाएंगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के आज तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे के बाद उन्होंने कहा कि सरकार विधायक ऐच्छिक निधि जारी करने पर भी विचार करेगी। इससे पूर्व, विधायक प्रकाश राणा के मूल प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने

कहा कि भविष्य में विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी करने पर विपक्ष के नेताओं से जल्द ही चर्चा की जाएगी। उन्होंने विधायक प्रकाश राणा द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि की अधिकांश राशि महिला मंडलों को जारी किए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि नियमों के तहत कुल राशि का केवल 10 फीसदी हिस्सा ही महिला मंडलों को जारी किया जा सकता है। इसके विपरीत प्रकाश राणा ने 5 सौ 43 महिला मंडलों को विधायक क्षेत्र विकास निधि बांट दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला मंडलों को यह राशि दी जा सकती है, लेकिन एक सीमा से अधिक नहीं। उन्होंने सलाह दी कि विधायक अपनी विधायक निधि को पूंजीगत कार्यों पर भी खर्च करे ताकि प्रदेश की जीएसडीपी में भी वृद्धि हो।

इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि विधानसभा द्वारा पारित बजट में शामिल है। उन्होंने सरकार से इस राशि को तुरंत जारी करने की भी मांग की और कहा कि विधायक इस निधि को अपने क्षेत्र के विकास पर ही खर्च कर रहे हैं, न कि व्यक्तिगत तौर पर। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा के दौरान टूटे रास्तों और अन्य विकास कार्यों के लिए विधायकों ने कई घोषणाएं कर रखी हैं, क्या उसके लिए राशि जारी नहीं होनी चाहिए। विधायक कुलदीप सिंह राठौर के प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश में सेब बागवानों को ठगी से बचाने के लिए राज्य सरकार लाइसैंस बनाने के लिए बैंक गारंटी की शर्त में बदलाव करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस राशि को बढ़ाएगी ताकि बागवानों से सेब खरीद कर कोई भी आढ़ती व लदानी फरार न हो सके। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य की तीन कृषि उपज मंडी समितियों में सेब खरीद के बाद भुगतान न करने के 3 सौ 79 मामले सामने आए हैं। इसमें कुल 8 करोड़ 5 लाख रुपये की देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इनमें से 69 मामलों में एक करोड़ 93 लाख 21 हजार से अधिक का भुगतान सेब उत्पादकों को दिला दिया है, जबकि शेष राशि अभी लंबित है।

राज्यसभा चुनाव तारीख

चुनाव आयोग ने आज 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में सात, तमिलनाडु में छह, बिहार और पश्चिम बंगाल में पांच–पांच, ओडिशा में चार, असम में तीन, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में दो–दो और हिमाचल प्रदेश में एक सीट रिक्त हो रही है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी का 9 अप्रैल को कार्यकाल पूरा हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 26 तारीख को जारी की जाएगी और नामांकन 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 16 मार्च को होगा। 20 मार्च से पहले चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी।

फागली उत्सव

जनजातीय जिला लाहौल स्पिति की पट्टन घाटी में फागली का त्यौहार हर्षोल्लास व पारम्परिक ढंग से मनाया गया। घाटी के लोगों ने अपने–अपने घरों में स्थापित स्थानीय देवी–देवताओं की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की और बड़े बुजुर्गों को फूल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फागली उत्सव को पट्टन घाटी में सामाजिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक माना जाता है और इस दिन दानवीर महाबली राजा बलि की पूजा की जाती है।

जुकारू उत्सव

उधर चम्बा जिला की पांगी घाटी में जुकारू पर्व आज शुरू हो गया है। ये त्यौहार लगभग 12 दिन तक चलता है। इस त्यौहार में विशेष रूप से बलदानों राजा की पूजा की जाती है और सुख–समृद्धि व धार्मिक परम्पराओं का प्रतीक ये त्यौहार भाईचारे की भावना का संदेश देता है। पांगी घाटी की शौर पंचायत के उप–प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने जुकारू पर्व पर घाटी के लोगों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।

कांग्रेस बैठक

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया है कि 20 फरवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हिमाचल कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मंत्रिमण्डल के सभी सदस्य, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल, सहप्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी भी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। विनय कुमार ने बताया कि इस बैठक में प्रदेश की ताजा राजनीति के साथ–साथ संगठन के गठन को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में 16वें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश का राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के बारे में केन्द्रीय आलाकमान को अवगत करवाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आर.डी.जी. के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मिलने का समय भी मांग जाएगा।